

संपादकीय

बढ़ती बेरोजगारी

आखिरकार मोदी सरकार ने मान लिया है कि बीते वर्ष में बेरोजगारी पिछले साढ़े चार दशकों में सबसे ऊंचे पायदान पर रही। नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जारी किये गये आंकड़े वही हैं, जिन्हें चुनाव से पहले लीक होने पर विवाद हुआ? था और सरकार ने आधे-अधूरे मानकर खारिज कर दिया था। जाहिर है सरकार चुनावी मुहिम पर बेरोजगारी के मुद्दे को हावी नहीं होना देना चाहती है। मगर यह देश में हर किसी की चिंता का विषय होना चाहिए कि पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक 6.1 प्रतिशत बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। इन आंकड़ों की अवधि वर्ष 2017-18 है।

इससे बढ़कर चिंता की बात यह है कि ये आंकड़े ऐसे समय पर स्वीकार किये जा रहे हैं जब देश की विकास दर पिछले पांच सालों में व्यूनतम स्तर 5.8 फीसदी है। वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में विकास दर 7.2 फीसदी मापी गई थी। ऐसे में सबल उठना स्वाभाविक है कि कहीं यह मंदी की आहट तो नहीं है। निःसंदेह कार्यभार संभालने के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को कई मोर्चों पर मुकाबला करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का दायित्व निर्वहन करना है। निश्चित रूप से विकास के इंजन को ईंधन देने से ही विकास दर व रोजगारों में वृद्धि हो सकती है। दरअसल नवीनतम आंकड़े इस मायने में भी चिंता का विषय हैं कि ये आंकड़े अर्थव्यवस्था की नकारात्मक तरवीर उकेरते हैं। हालांकि सरकार की अपनी दलीलें हैं और वह प्रति व्यक्ति खपत बढ़ने को बेरोजगारी से नहीं जोड़ती। यानी रोजगार संगठित क्षेत्र में न हों मगर रोजगार असंगठित क्षेत्र में आकार ले रहे हैं। यह एक हकीकत है कि नोटबंदी व जीएसटी का असंगठित क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। बैंगलुरु स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ सर्टेनेबल एंप्लॉयमेंट द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार नोटबंदी के बाद के दो वर्षों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पचास लाख लोगों ने अपने रोजगार से हाथ थोया है।

इसमें दो राय नहीं कि श्रम प्रधान देश भारत में रोजगार का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र द्वारा ही सुजित किया जाता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों के चलते जो पढ़े-लिखे लोग नौकरी की तलाश में निकलते हैं, वे आधुनिक उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। मजबूरी में वे असंगठित क्षेत्रों में छोटी-मोटी नौकरियों में संतुष्ट होकर रह जाते हैं। नोटबंदी की बाद बच्ची-खुची कसर जीएसटी के फियान्वयन में व्याप्त विसंगतियों ने पूरी कर दी। कुल भिलाकर रोजगार सेक्टर अभी तक इन झटकों से उबर नहीं पाया है। बेरोजगारी के हालिया आंकड़ों का चिंताजनक पहलू यह भी है कि बेरोजगारी का दायरा शहरों में ज्यादा चिंताजनक है, जो 7.8 फीसदी बताया जाता है।

'ए ब्रेड टोस्ट' बनाने की विधि...



सामग्री :

1 अंडा, जूसरत भर पानी, एक टेबलस्पून क्वाइट विनेगर, 4 टीस्पून ऐस्प्रैगेस पेस्ट, थोड़े चिकेन की पतली स्लाइस, 1 पीस फेंच ब्रेड, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, कुछ हब्स

विधि :

सॉसपैन में पानी और विनेगर तेल डालकर ऐस्प्रैगेस पेस्ट डालकर उबाल अनेंद्र। अब अंडा डालकर भूंहें। ध्यान रखें, अंडे को सिर्फ पोच करना है, इसे उबालना नहीं है। अब नमक, काली मिर्च को दोनों तरफ से हलका सेंक लें। घीलकर अलग रखें। अब उसी पैन में

अगले 3 सालों तक दुनिया की सबसे तेज तरवरी करने वाला देश रहेगा भारत: विश्व बैंक

वॉर्सिंगटन (आरएनएस)। भारत आने वाले समय में सबसे ऊंचे पायदान पर रही। नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जारी किये गये आंकड़े वही हैं, जिन्हें चुनाव से पहले लीक होने पर विवाद हुआ? और सरकार ने आधे-अधूरे मानकर खारिज कर दिया था। जाहिर है सरकार चुनावी मुहिम पर बेरोजगारी के मुद्दे को हावी नहीं होना देना चाहती है। मगर यह देश में हर किसी की चिंता का विषय होना चाहिए कि पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक 6.1 प्रतिशत बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। इन आंकड़ों की अवधि वर्ष 2017-18 है।

कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़े सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें किया गया है। इसके अनुसार, बेहतर निवेश तथा चौथी खपत के दम पर अगले तीन साल तक भारत की अर्थव्यवस्था पर आ गई। यह चीन के छह प्रतिशत की तुलना में बढ़ रहा है, जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक होगी। विश्व बैंक की विषय में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत तथा चौथी खपत की विषय में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.50 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

जिमेदार बताया था। विश्व बैंक ने मंगलवार को जारी अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के 7.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का अनुमान है।

दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ष 2021 तक भारत की अर्थिक वृद्धि दर चीन के छह प्रतिशत की तुलना में डेढ़ प्रतिशत अधिक होगी। विश्व बैंक के अनुसार, 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रही। इस दर के गिरकर 2019 में 6.20 प्रतिशत, 2020 में 6.10 प्रतिशत और 2021 में 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके साथ ही विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में वृद्धि दर के लिये



इसके बाद अगले दो वित्त वर्ष तक वृद्धि दर की यही गति बरकरार रहने वाली है। उसने कहा, "मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के लक्ष्य से से जीर्चे हैं जिससे मौद्रिक नीति सुगम रहेगी। इसके साथ ही ब्रैश की वृद्धि दर के मजबूत होने से निजी उपभोग एवं निवेश को फायदा होगा।"

अंतरिम बजट में किए गए आवंटन को बरकरार रखेगा वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को अंतरिम बजट में किए गए आवंटन को चालू वित्त वर्ष के लिए अंतिम बजट में भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। अंतिम बजट लोकसभा में पांच जुलाई को पेश किया जाना है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। अब चूंकि निर्मला सीतारमण की बजट टीम में वित्त वर्ष (राज्य) मंत्री अनुराग सिंह तारुर और मुख्य अर्थिक सलाहकार कृष्णार्थ सुब्रमण्यम शामिल हैं। आधिकारिक टीम की अग्रवाल वित्त सचिव सुधार चंद्र गांग, खर्च सचिव गिरेश चंद्र मुर्म, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, दीपम सचिव अतनु चक्रवर्ती और वित्तीय मामलों के सचिव गजीब कुमार करेंगे।

एनईएफटी और आरटीजीएस पर नहीं लगेगा कोई चार्ज

» आरबीआई का बड़ा फैसला

मुंबई (आरएनएस)। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रिएल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फॉंस ट्रांसफर (एनईएफटी) को निश्चिल करने का फैसला किया जाता है। इसके बाद बैंकों को भी अन्तरालान लेनदेन तीन तरीके से जिया जाता है। आरटीजीएस और एनईएफटी के अलावा चार अर्थमपरीएस यानी तकाल भूगतान सेवा की भी एक प्रणाली है। जिसका शुल्क एनईएफटी से ज्यादा होता है। जबकि आरटीजीएस के लिए लोन में आरटीजीएस के बारे में आईएफटी का बड़ा फैसला

ब्यान' में कहा गया है कि इसके बारे में और एनईएफटी प्रणाली के जरिए हुए लेनदेन के लिए बैंकों से शुल्क लेता है जा एंगे। ब्यान के अनुसार, डिजिटल लेनदेन को बड़ा बदलाव देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस और एनईएफटी को शुल्क मुक्त बनाने का फैसला किया जाता है। आरटीजीएस और एनईएफटी के अलावा आईएमपीएस यानी तकाल भूगतान सेवा की भी एक प्रणाली है। जिसका शुल्क एनईएफटी से ज्यादा होता है। ब्यान में आरटीजीएस के लिए हो सकता है।

फिलहाल आरबीआई आरटीजीएस



कुछ नहीं कहा गया है। आरटीजीएस सिफर दो लाख रुपये या उससे ज्यादा की राशि के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि आईएमपीएस का इस्तेमाल सिफर दो लाख रुपये तक के लेनदेन के लिए हो सकता है।

फिएट क्राइसलर

ने रेनो के साथ

विलय का प्रस्ताव

वापस लिया

पेरिस (आरएनएस)।

फिएट क्राइसलर ने ब्रह्मसतिवार को कहा कि उसने रेनो के साथ विलय का प्रस्ताव वापस ले लिया है। उसने कहा कि फ्रांस की सरकार के साथ किसी समझौते पर पहुंचना मुश्किल होगा। फिएट क्राइसलर ने एक बायान में कहा कि वह अपनी पेशकश के हितों के प्रति प्रौद्योगिक तरह आश्रित नहीं है। लेकिन फ्रांस में अभी ऐसे राजनीतिक कार्यों के लिए धब्बा लेना चाहिए।

कार्ल्स- धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए धब्बा लेना चाहिए। व्यापारियों और लिंगों के साथ वाद-विवाद का योग है। व्यवहार में आधारिकता देखने की मिलेगी।